राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम

योजना के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) की शुरूआत एवं उद्घाटन प्रधान मंत्री ने कानपुर (उत्तर प्रदेश) में अगस्त 1996 में की थी । राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेशों को शहरी स्लम क्षेत्रों का विकास करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी की जा रही थी । इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलापूर्ति, बरसाती जल निकासी, समुदाय स्नान घर, मौजूदा लाइनों को चौड़ा करने एवं नई लाइनें बिछाने, सीवरेज, सामुदायिक शौचालयों एवं सड़क पर बिजली की व्यवस्था इत्यादि जैसी भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए शहरी सलम बस्तियों का सुधार करना था । इसके अलावा एनएसडीपी के तहत फंड राशियों को पूर्व स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसूति, बाल स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य जिसमें जरूरी दवाओं को पिलाना शामिल है इत्यादि जैसी सामाजिक सुविधाओं एवं सामुदायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पर खर्च किया जा सकता है । इस कार्यक्रम में आश्रय उन्नयन तथा नए मकानों का निर्माण भी एक हिस्से के रूप में था ।

इस कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश की स्लम आबादी के आधार पर योजना आयोग ने वार्षिक रूप से फंड राशि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किया था । वित्त मंत्रालय ने राज्यों को फंड की राशि जारी की थी और गृह मंत्रालय ने संघ शासित प्रदेशों को फंड जारी किए थे । राज्य सरकारों ने क्रियान्वयक एजेंसियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप फंड की राशि आगे जारी की थी । राज्यों में इस कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने के लिए शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया था ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को नीचे दर्शाए गए अनुसार वर्ष 1996-97 से 2004-05 के दौरान कुल 3089.63 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई थी :-

क्रम सं.	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	1996-97	250.01
2	1997-98	290.99
3	1998-99	351.63
4	1999-2000	384.96
5	2000-2001	247.34
6	2001-2002	282.40
7	2002-2003	333.44
8	2003-2004	335.08
9	2004-2005	613.78
	कुल	3089.63

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2005-06 से समाप्त कर दिया गया ।

जैसा कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने सूचित किया है, इस कार्यक्रम की स्थापना से लेकर 31.8.2006 तक केन्द्र सरकार ने 3089.63 करोड़ रुपये का कुल फंड जारी किया था, जिसमें से 2496.18 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है और इस कार्यक्रम से लगभग 4.58 करोड़ स्लमवासियों को लाभ पहुंचा है ।